Drishti IAS

करेंट अफेयर्स उत्तराखंड

दिसंबर 2023 (संग्रह)

Drishti, 641, First Floor, Dr. Mukharjee Nagar, Delhi-110009
Inquiry (English): 8010440440, Inquiry (Hindi): 8750187501
Email: help@groupdrishti.in

अनुक्रम

उत्तराखंड **3**

- बद्रीनाथ हाईवे पर होगा प्रदेश का पहला सिग्नेचर ब्रिज 3
- केंद्र सरकार ने जोशीमठ के पुनर्निर्माण के लिये रिकवरी एंड रिकंस्ट्रक्शन योजना को मंज़ूरी दी 3
- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक की प्रमुख निर्णय 4
- प्रदेश सरकार ने पहली उत्तराखंड हेलीपैड व हेलीपोर्ट नीति को मंज़ूरी दी 5
- लोहाघाट में बनेगा प्रदेश का पहला बालिका स्पोर्ट्स कॉलेज 6
- आपदा से बचाव के लिये उत्तराखंड में काम करेगा इंसिडेंट रिस्पॉन्स सिस्टम 7
- एनर्जी कॉन्क्लेव में हुए 40 हज़ार करोड़ रुपए से अधिक के एमओयू 7
- उत्तराखंड देश का पहला राज्य जिसे एक दिन में सबसे अधिक 18 जीआई टैग मिले 8
- अब सीधे पीएमओ से जुड़ेंगी उत्तराखंड की 697 ग्राम पंचायतें 9
- उत्तराखंड में अब स्कूली बच्चों को आधार की तरह जारी होगा परमानेंट एजुकेशन नंबर 10
- उत्तराखंड में जल्द शुरू होगी जायरो कॉप्टर सफारी 10
- प्रदेश में खुलेंगे 10 निजी विश्वविद्यालय, तीन नए मेडिकल कॉलेज 11
- आईएमए पासिंग आउट परेड 2023: भारत के 343 और मित्र राष्ट्रों के 29 कैडेट्स पास आउट हुए 11
- 7708 करोड़ रुपए की लागत से पूर्ण होगा टिहरी झील विकास परियोजना 13
- ज्वालापुर में बनेगा यूनिटी मॉल, शामिल होगी सभी राज्यों की एक-एक दुकान 14
- मिनी गैस एजेंसी योजना 15
- राज्यस्तरीय प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को राष्ट्रीय खेलों में मिलेगी सीधे एंट्री 15
- राज्य की विद्युत व्यवस्था और पॉवर ट्रांसमिशन नेटवर्क की मजबूती हेतु एशियन विकास बैंक ने 200 मिलियन डॉलर की ऋण को स्वीकृति दी 16
- उत्तराखंड से हुई देश की पहली हिमालयी एयर सफारी की शुरूआत 16
- उत्तराखंड को मिला साहसिक पर्यटन में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार 17
- उत्तराखंड को साहसिक पर्यटन में सर्वश्रेष्ठ राज्य का मिला पुरस्कार 18
- उत्तराखंड में सड़कों से जुड़ेंगे 100 से अधिक जनसंख्या वाले जनजातीय क्षेत्र 19
- पांच हज़ार मिनी आंगनबाड़ी केंद्र होंगे उच्चीकृत 20
- उत्तराखंड में सख्त भूमि कानून 20
- टिहरी में अनेक परियोजनाएँ 21
- चंपावत में विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर 21
- उत्तराखंड में जानवरों के हमले 22
- उत्तराखंड 'विंटर कार्निवाल' 23

नोट :

उत्तराखंड

बद्रीनाथ हाईवे पर होगा प्रदेश का पहला सिग्नेचर ब्रिज

चर्चा में क्यों ?

3 दिसंबर, 2023 को राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण खंड लो.नि.वि., श्रीनगर गढ़वाल के अधिशासी अभियंता तनुज कांबुज ने बताया कि बद्रीनाथ हाईवे पर नरकोटा में प्रदेश के पहले सिग्नेचर ब्रिज का कार्य तेजी से किया जा रहा है।

प्रमुख बिंदु

- विदित हो कि ऋषिकेश-बद्रीनाथ हाईवे पर नरकोटा में उत्तराखंड राज्य का पहला घुमावदार पुल बनाया जा रहा है। ऑल वेदर रोड परियोजना के तहत 64 करोड़ रुपए की लागत से 110 मीटर लंबे पुल का निर्माण किया जा रहा है।
- इस सिग्नेचर ब्रिज से मई 2024 तक वाहनों के संचालन का लक्ष्य रखा गया है।
- ऋषिकेश-बदरीनाथ हाईवे पर नरकोटा गदेरे पर घुमावदार मोटर पुल का निर्माण किया जा रहा है। इसकी सुरक्षा के लिये दोनों तरफ के साथ ऊपरी की तरफ से सुरक्षा केबल रहेगी। इस सिग्नेचर पुल की बनावट ही इसका प्रमुख आकर्षण होगी।

केंद्र सरकार ने जोशीमठ के पुनर्निर्माण के लिये रिकवरी एंड रिकंस्ट्रक्शन योजना को मंज़ूरी दी

चर्चा में क्यों ?

30 नवंबर, 2023 को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता वाली उच्चस्तरीय समिति ने भू धंसाव से ग्रस्त जोशीमठ के पुनर्निर्माण के लिये 1658.17 करोड़ रुपए की रिकवरी एंड रिकंस्ट्रक्शन योजना को मंज़ूरी दी।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- विदित हो कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री शाह से प्रस्ताव को मंज़ूरी देने का अनुरोध किया था।
- योजना के तहत राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) की रिकवरी एवं रिकंस्ट्रक्शन विंडो से 1079.96 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता दी जाएगी।
- राज्य सरकार राहत के लिये राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) से 126.41 करोड़ रुपए और राज्य के बजट से 451.80 करोड़ रुपए देगी। इसमें पुनर्वास के लिये 91.82 करोड़ भूमि अधिग्रहण की लागत शामिल है।
- प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में जोशीमठ के पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण योजना के लिये 1000 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया है।
- राज्य ने केंद्र सरकार से जोशीमठ के पुनर्निर्माण एवं पुनर्वास योजना के लिये 2942.99 करोड़ रुपए का पैकेज मांगा था। इसमें 150 पूर्व-निर्मित घरों का निर्माण, साइट विकास कार्य, अंतरिम राहत, आवासीय और वाणिज्यिक बुनियादी ढाँचे को नुकसान के लिये मुआवजा, असुरक्षित क्षेत्र में आने वाले परिवारों की भूमि के लिये मुआवजा, प्रभावित लोगों का स्थायी पुनर्वास और अधिग्रहण और विकास शामिल है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक की प्रमुख निर्णय

चर्चा में क्यों ?

4 दिसंबर, 2023 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 250 से कम आबादी वाले 3177 गाँवों को मुख्य सड़क से जोड़ने के लिये 'मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना' को मंज़ूरी देने के साथ ही कई अन्य महत्त्वपूर्ण निर्णय लिये गए।

प्रमुख बिंदु

- कैबिनेट ने माध्यमिक शिक्षा विभाग को प्रति वादन के हिसाब से सहायक अध्यापक और प्रवक्ता रखने की अनुमति दे दी है। ऐसे 1500 से 2000 शिक्षक रखे जा सकेंगे।
- कैबिनेट ने वर्ष 2009 से वर्ष 2016-17 के दौरान आवेदन के बावजूद 'कन्याधन योजना' के लाभ से वंचित रह गईं 35088 बेटियों को लाभ देने का फैसला किया है। उन्हें 15,000 की दर से धनराशि मिलेगी। इस पर सरकार 52 करोड़ 63 लाख रुपए खर्च करेगी।

नोट :

- छात्र-छात्राओं को आधुनिक और गुणवत्तायुक्त शिक्षा देने के लिये प्रदेश में 559 उत्कृष्ट विद्यालयों की स्थापना होगी। उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में ऐसे विद्यालय का चयन किया जाएगा, जिसके 15 किमी. की परिधि में अधिक-से-अधिक राजकीय हाईस्कूल एवं राजकीय इंटर कॉलेज संचालित हों। इन पर 240 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
- जहाँ सरकारी जमीन उपलब्ध नहीं है, वहाँ निजी भूमि पर हेलिपेड बनाने के लिये प्रोत्साहन नीति को मंज़ूरी दे दी गई है। नीति के तहत हेलिपेड बनाने पर 50 प्रतिशत अनुदान मिलेगा। लीज पर भूमि भी दी जा सकती है।
- कैबिनेट ने वर्चुअल रजिस्ट्री की नीति को मंज़ूरी दे दी है। इसके तहत अब घर बैठे ऑनलाइन रजिस्ट्री कराई जा सकेगी। व्यक्ति को कार्यालय में आने की आश्यकता नहीं होगी।
- कैबिनेट ने पिथौरागढ़ और हरिद्वार में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेजों में 100-100 एमबीबीएस प्रशिक्षु क्षमता के संचालन के लिये 950-950 पदों के ढाँचे को मंज़ूरी दी है।
- अब प्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस बनाए जाने पर परिवहन विभाग आवेदक से 100 रुपए यूजर चार्ज वसूलेगा। इससे लाइसेंस बनवाना कुछ महँगा हो जाएगा। कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंज़ूरी दी है।

प्रदेश सरकार ने पहली उत्तराखंड हेलीपैड व हेलीपोर्ट नीति को मंज़ूरी दी

चर्चा में क्यों ?

4 दिसंबर, 2023 को उत्तराखंड राज्य सरकार ने प्रदेश में एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिये पहली उत्तराखंड हेलीपैड व हेलीपोर्ट नीति को मंज़ूरी दी है। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ ही आपातकालीन चिकित्सा और आपदा के दौरान बचाव व राहत कार्यों में आसानी होगी।

प्रमुख बिंदु

- प्रदेशभर में कई ऐसे स्थान हैं, जहाँ पर हेलीपैड या हेलीपोर्ट विकसित किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर सरकारी ज़मीन उपलब्ध नहीं है। इसके लिये सरकार ने निजी भूमि पर हेलीपैड व हेलीपोर्ट बनाने की नीति को मंज़ूरी दी है।
- नीति में हेलीपैड व हेलीपोर्ट के लिये ज़मीन देने के लिये भू-स्वामी को दो विकल्प दिये गए हैं-
  - पहला, भूस्वामी ज़मीन को 15 साल के लिये उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण (यूकाडा) को लीज़ पर दे सकता है, जिसमें यूकाडा डीजीसीए नियमों के तहत हेलीपैड को विकसित करेगा। इसके लिये बदले भू-स्वामी को प्रति वर्ष 100 रुपए प्रति वर्गमीटर के हिसाब से किराया दिया जाएगा। इसके अलावा संचालन एवं प्रबंधन से प्राप्त होने वाले राजस्व का 50 प्रतिशत भुगतान किया जाएगा।

नोट :

- दूसरा, भू-स्वामी स्वयं भी हेलीपैड व हेलीपोर्ट को विकसित कर सकता है। इसके लिये डीजीसीए से लाइसेंस लेकर हेलीपैड का इस्तेमाल करने वालों से शुल्क लेगा। सरकार की ओर से कुल पूंजीगत व्यय पर 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी।

- नीति में हेलीपैड के लिये कम-से-कम 1,000 वर्गमीटर और हेलीपोर्ट के लिये 4,000 वर्गमीटर ज़मीन अनिवार्य है। हेलीपैड बनाने के लिये 10 से 20 लाख रुपए तक खर्च और हेलीपोर्ट निर्माण में दो से तीन करोड़ रुपए खर्च का अनुमान है। यदि भूस्वामी स्वयं हेलीपैड व हेलीपोर्ट बनाता है तो इस पर सरकार सब्सिडी देगी, जिसका भुगतान दो किस्तों में किया जाएगा।

लोहाघाट में बनेगा प्रदेश का पहला बालिका स्पोर्ट्स कॉलेज

चर्चा में क्यों ?

5 दिसंबर, 2023 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स में आयोजित समारोह में कहा कि लोहाघाट में प्रदेश का पहला बालिका स्पोर्ट्स कॉलेज बनेगा, इसके लिये 500 नाली भूमि हस्तांतरण के लिये अनुमोदन दिया जा चुका है।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समारोह में 37वें राष्ट्रीय खेलों के पदक विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया तथा खेल मंत्री रेखा आर्य ने मुख्यमंत्री को 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी के लिये भारतीय ओलंपिक संघ का ध्वज सौंपा, जिसे राष्ट्रीय खेल सचिवालय रायपुर में स्थापित किया गया।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। गुजरात में 36वें राष्ट्रीय खेलों में राज्य के खिलाड़ियों ने 18 पदक जीते, जबकि इस साल गोवा में 37वें राष्ट्रीय खेलों में खिलाड़ियों ने 24 पदक जीते।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि गाँवों में ओपन जिम के लिये 10 करोड़ रुपए के बजट की व्यवस्था की गई है, जबकि विश्वविद्यालयों में व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिये सरकार पाँच प्रतिशत स्पोर्ट्स कोटे को लेकर नियमावली बनाने जा रही है।
- उन्होंने कहा कि निजी खेल क्षेत्रों के माध्यम से खेल अवस्थापना सुविधाओं के निर्माण के लिये अनुदान दिए जाने की भी व्यवस्था की गई है। खिलाड़ियों के लिये सरकारी नौकरी में चार प्रतिशत खेल कोटे की प्रक्रिया अंतिम चरण में है।

नोट :

आपदा से बचाव के लिये उत्तराखंड में काम करेगा इंसिडेंट रिस्पॉन्स सिस्टम

चर्चा में क्यों ?

5 दिसंबर, 2023 को आपदा प्रबंधन सचिव डॉ. रंजीत सिन्हा ने प्रेस वार्ता में बताया कि आपदा में लोगों को तेजी से बचाने, राहत पहुँचाने के लिये इंसिडेंट रिस्पॉन्स सिस्टम (आईआरएस) तैयार किया जा रहा है।

प्रमुख बिंदु

- डॉ. रंजीत सिन्हा ने बताया कि उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (यूएसडीएमए) ने इसकी कवायद शुरू कर दी है। इसकी स्थापना राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) के नियमों के तहत की जा रही है।
- इसके लिये यूएसडीएमए ने निविदा जारी की है। ब्लॉक से लेकर ज़िला व राज्य स्तर पर इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम (आईआरटी) भी बनाई जाएगी। आपदा के हिसाब से ये टीम भी काम करेंगी।
- आईआरएस की गाइडलाइन तैयार कर ली गई है। इसे लागू करने के लिये सॉफ्टवेयर बनवाया जा रहा है। इसके बाद आपदा प्रबंधन में और बेहतर तरीके से राहत एवं बचाव के कार्य किये जा सकेंगे।
- विदित हो कि राज्य में हर साल आपदाएँ सरकार के लिये चुनौती साबित होती हैं। हाल में सिलक्यारा सुरंग हादसा हो या उससे पहले जोशीमठ भूधंसाव जैसी आपदा। इनसे पार पाने के लिये एनडीएमए के नियमों के तहत अब आईआरएस सिस्टम तैयार किया जा रहा है। इससे आपदा की तीव्रता या जोखिम के हिसाब से तत्काल बचाव व समाधान किया जा सकेगा।
- आईआरएस के तीन सेक्शन होंगे। एक ऑपरेशन सेक्शन होगा। दूसरा प्लानिंग सेक्शन और तीसरा लॉजिस्टिक सेक्शन होगा। तीनों के समन्वय से आपदा राहत कार्यों को और तेजी से किया जा सकेगा।
- प्रारंभिक चेतावनी मिलने के बाद रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर (आरओ) संबंधित क्षेत्र की इंसिडेंट रिस्पांस टीम (आईआरटी) को सक्रिय करेगा। बिना किसी चेतावनी के किसी आपदा की स्थिति में स्थानीय आईआरटी काम करेगा। अगर ज़रूरी होगा तो वह आरओ को सहायता के लिये संपर्क करेगा।
- आईआरटी सभी स्तरों, यानी राज्य, ज़िला, उप-मंडल और तहसील, ब्लॉक पर पूर्व-निर्धारित होगी। अगर आपदा जटिल होगी और स्थानीय आईआरटी के नियंत्रण से बाहर होगी तो उच्चस्तरीय आईआरटी को सूचित किया जाएगा। इसके बाद उच्चस्तरीय आईआरटी इस पूरी आपदा से बचाव का ज़िम्मा संभालेगी।

एनर्जी कॉन्क्लेव में हुए 40 हज़ार करोड़ रुपए से अधिक के एमओयू

चर्चा में क्यों ?

5 दिसंबर, 2023 को डेस्टिनेशन उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के तहत सचिवालय में हुए एनर्जी कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में 40 हज़ार करोड़ रुपए से अधिक के एमओयू किये गए।

प्रमुख बिंदु

- डेस्टिनेशन उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के तहत सचिवालय में एनर्जी कॉन्क्लेव में विभिन्न कंपनियों के प्रतिनिधि पहुँचे। करीब 33 कंपनियों ने राज्य में सौर ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, गैस आधारित ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश के लिये ये समझौते किये हैं।
- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में 40,423 करोड़ रुपए के एमओयू किये गए। इनमें से 21,522 करोड़ की ग्राउंडिंग हो चुकी है, जबकि 18901 करोड़ के नए एमओयू किये गए हैं।
- मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य में ऊर्जा के क्षेत्र में कार्य करने के लिये अपार संभावनाएँ हैं। निवेश बढ़ाने के लिये सरकार लगातार प्रयास कर रही है। औद्योगिक जगत से जुड़े लोगों के सुझावों के आधार पर 27 नई नीतियाँ बनाई गई हैं और अनेक नीतियों को सरल किया गया है।

नोट :

- इस मौके पर आई कंपनियों ने सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट, हाइड्रो पॉवर प्रोजेक्ट, पंप स्टोरेज प्लांट, सीएनजी प्लांट, सोलर पार्क बनाने के प्रस्ताव दिए। टीएचडीसी-यूजेवीएनएल संयुक्त उपक्रम ने सर्वाधिक 16370 करोड़ रुपए के एमओयू किये हैं। वहीं जीएमआर ने 10,800 करोड़ रुपए, यूजेवीएनएल ने 3220 करोड़ रुपए, इवॉल्व एनर्जी ने 1184 करोड़ रुपए तथा कुंदनग्रुप और भिलंगना हाइड्रो पॉवर ने 1000-1000 करोड़ रुपए के एमओयू किये हैं।

उत्तराखंड देश का पहला राज्य जिसे एक दिन में सबसे अधिक 18 जीआई टैग मिले

चर्चा में क्यों ?

4 दिसंबर, 2023 को उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया, जिसे एक दिन में सबसे अधिक 18 उत्पादों पर जीआई प्रमाण-पत्र मिले हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में आयोजित कार्यक्रम में जीआई प्रमाण-पत्रों का वितरण किया।

प्रमुख बिंदु

- अब तक उत्तराखंड के कुल 27 उत्पादों को जीआई टैग मिल चुका है।
- राज्य के जिन 18 उत्पादों को जीआई (जियोग्राफिकल इंडिकेशन) प्रमाण-पत्र मिले हैं, उनमें उत्तराखंड- चौलाई, झंगोरा, मंडुआ, लाल चावल, अल्मोड़ा लखौरी मिर्च, बेरीनाग चाय, बुरांस शरबत, रामनगर (नैनीताल) लीची, रामगढ़ आड़ू, माल्टा, पहाड़ी तोर, गहथ, काला भट्ट, बिच्छूबूटी फैब्रिक, नैनीताल मोमबत्ती, कुमाऊँनी रंगवाली पिछोड़ा, चमोली रम्माण मास्क तथा लिखाई वुड कार्विंग शामिल हैं।
- विदित हो कि उत्तराखंड के 9 उत्पादों- तेजपात, बासमती चावल, ऐपण आर्ट, मुनस्यारी का सफेद राजमा, रिंगाल क्राफ्ट, थुलमा, भोटिया दन, च्यूरा ऑयल तथा ताम्र उत्पाद को पहले ही जीआई प्रमाण-पत्र प्राप्त हो चुका है।
- वर्ष 2003 में जीआई कानून बनने से लेकर 2023 तक के 20 वर्षों के सफर में पहली बार एक दिन में एक साथ किसी राज्य के 18 उत्पादों को जीआई प्रमाण-पत्र निर्गत किये गए हैं।
- मुख्यमंत्री ने आशा व्यक्त की है कि जीआई टैग युक्त उत्तराखंड के उत्पादों का निर्यात तेजी से बढ़ेगा।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के सभी 13 जिलों में स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 'एक ज़िला, दो उत्पाद' योजना पर तेजी से कार्य चल रहा है।
- सभी ज़िलों में वहाँ के स्थानीय उत्पादों को पहचान कर उनके अनुरूप परंपरागत उद्योगों का विकास करना योजना का मुख्य उद्देश्य है। इससे स्थानीय काश्तकारों एवं शिल्पकारों के लिये स्वरोज़गार के अवसर बढ़ रहे हैं और हर ज़िले के स्थानीय उत्पादों को विश्वस्तरीय पहचान मिल रही है।

नोट :

- कृषि एवं उद्यान मंत्री गणेश जोशी ने इसे महत्त्वपूर्ण उपलब्धि बताते हुए कहा कि आगामी 12 से 18 जनवरी, 2024 तक देहरादून में प्रदेश स्तरीय जीआई टैग महोत्सव का आयोजन किया जाएगा।

अब सीधे पीएमओ से जुड़ेंगी उत्तराखंड की 697 ग्राम पंचायतें

चर्चा में क्यों ?

6 दिसंबर, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तराखंड की 697 ग्राम पंचायतें प्रधानमंत्री कार्यालय से सीधे जुड़ सकेंगी।

प्रमुख बिंदु

- इसके लिये भारतनेट के तहत सेटअप लगने के बाद यूपीसीएल बिजली के कनेक्शन दे रहा है। अब तक 200 से ज्यादा ग्राम पंचायतों को कनेक्शन दिया जा चुका है।
- भारतनेट योजना के तहत इन गाँवों तक ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाए गए थे, लेकिन बिजली कनेक्शन न होने से यहाँ इंटरनेट सेवाएँ उपलब्ध नहीं हो पा रहीं थी।
- इंटरनेट सेवाएँ चलने के बाद जहाँ केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के लिये आवेदन की सुविधा ग्राम पंचायत में ही मिल जाएगी।
- वहीं युवाओं को भी सरकारी नौकरी के आवेदन, विभिन्न योजनाओं के आवेदन का मौका यहाँ मिल सकेगा।

नोट :

उत्तराखंड में अब स्कूली बच्चों को आधार की तरह जारी होगा परमानेंट एजुकेशन नंबर

चर्चा में क्यों ?

6 दिसंबर, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तराखंड में अब स्कूली बच्चों को आधार की तरह परमानेंट एजुकेशन नंबर जारी किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- वर्तमान में कक्षा 9 और कक्षा 11वीं में बच्चों को स्कूल में पंजीकरण करना होता है।
- लेकिन, यूडाईज पोर्टल अपडेट होने के बाद कक्षा एक से ही बच्चे को एक परमानेंट एजुकेशन नंबर जारी कर दिया जाएगा, जो 12वीं तक मान्य रहेगा।
- भविष्य में किसी भी स्कूल से बच्चों की गलत या फर्जी टीसी जारी न हो, इसके लिये परमानेंट एजुकेशन नंबर (पीईएन) के आधार पर ही बच्चों को टीसी जारी की जाएगी।
- पोर्टल में न सिर्फ बच्चों, बल्कि स्कूल व शिक्षकों का डाटा भी उपलब्ध कराना होगा।
- पोर्टल में शिक्षकों का डाटा अपलोड होने के बाद एक शिक्षक सिर्फ एक ही स्कूल में पढ़ा सकेगा। जबकि, विद्यार्थियों से जुड़ी सभी जानकारी इस पोर्टल पर स्कूल ही अपलोड करेगा।

उत्तराखंड में जल्द शुरू होगी जायरो कॉप्टर सफारी

चर्चा में क्यों ?

10 दिसंबर, 2023 को राजस एयरो स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर लिमिटेड (RAAAPL) के सीईओ मनीष सैनी ने बताया कि जल्द ही उत्तराखंड में जायरो कॉप्टर सफारी शुरू की जाएगी।

प्रमुख बिंदु

- मनीष सैनी ने बताया कि RAAAPL ने ऋषिकेश में 2013-14 में एयर सफारी शुरू की थी। यह इंडिया की पहली एयर सफारी थी।
- उन्होंने बताया कि इसी माह राज्य में जायरो कॉप्टर सेवा की शुरुआत भी की जा रही है, जो भारत और दक्षिण एशिया की पहली जायरो कॉप्टर सफारी होगी।
- गौरतलब हो कि राजस एयरोस्पोर्ट्स एंड एडवेंचर लिमिटेड (RAAAPL) एक प्राइवेट लिमिटेड भारतीय गैर-सरकारी कंपनी है, जिसे 30 मई, 2013 को भारत में निगमित किया गया था और इसका पंजीकृत कार्यालय पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखंड में है।

नोट :

- यह कॉर्पोरेट कला मनोरंजन और मनोरंजन सेवाएँ प्रदान करने के व्यवसाय में लगा हुआ है। वर्तमान में राजस एयरोस्पोर्ट्स मसूरी के जॉर्ज एवरेस्ट से हिमालयन दर्शन हेलिकॉप्टर सेवा संचालित कर रही है।

प्रदेश में खुलेंगे 10 निजी विश्वविद्यालय, तीन नए मेडिकल कॉलेज

चर्चा में क्यों ?

9 दिसंबर, 2023 को उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने वैश्विक निवेशक सम्मेलन में निवेशकों को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तराखंड में 10 नए निजी विश्वविद्यालय और तीन नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे।

प्रमुख बिंदु

- शिक्षा मंत्री ने कहा कि नए स्कूल और विश्वविद्यालयों के लिये सरकार सभी बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध कराएगी। राज्य में निवेशकों को स्कूल और विश्वविद्यालय के लिये ज़मीन का चयन खुद करना है। बिजली, पानी, सड़क की सुविधा सरकार देगी। 25 प्रतिशत सब्सिडी भी दी जाएगी।
- उन्होंने निवेशकों से पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, पौड़ी आदि पर्वतीय ज़िलों में निवेश करने के लिये कहा।
- उन्होंने बताया कि राज्य सरकार का लक्ष्य है कि उत्तराखंड में 2024 तक पाँच लाख बच्चे अन्य राज्यों से पढ़ने आएँ, जबकि एक लाख विदेशी बच्चे यहाँ आकर पढ़ें।
- विदित हो कि वैश्विक निवेशक सम्मेलन में शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा में 9000 करोड़ रुपए के निवेश का करार हुआ। इसमें करीब 17 निजी उच्च शिक्षण संस्थान और चार माध्यमिक विद्यालय शामिल थे।
- इसमें अपोलो ग्रुप, साबरमती इंस्टीट्यूट गुजरात, सलोनी यूनिवर्सिटी, दून मॉर्डन एजुकेशन सोसाइटी, न्यू फाउंडेशन, शिवालिक हिल फाउंडेशन, डीआईटी यूनिवर्सिटी, गोंडवाना रिसर्च फाउंडेशन, राइट पार्क फाउंडेशन, ग्रीन फील्ड स्कूल, जन कल्याण एजुकेशन, गुरुनानक ट्रस्ट रुड़की, उत्तराखंड उत्थान समिति आदि के बीच करार हुआ।

आईएमए पासिंग आउट परेड 2023: भारत के 343 और मित्र राष्ट्रों के 29 कैडेट्स पास आउट हुए

चर्चा में क्यों ?

9 दिसंबर, 2023 को भारतीय सैन्य अकादमी (आईएमए) देहरादून में पासिंग आउट परेड में 343 भारतीय कैडेट्स और बारह मित्र देशों के 29 विदेशी कैडेट पास आउट हुए। श्रीलंका के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल शैवेंद्र सिल्वा ने परेड की सलामी ली।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- भारतीय सैन्य अकादमी (आईएमए) में पासिंग आउट परेड में देश और विदेश के 372 कैडेट्स अफसर बनकर अपनी सेनाओं की मुख्य धारा में जुड़ गए। इनमें 343 अफसर भारतीय सेना को मिले।
- आईएमए की स्थापना के बाद से अब तक यहाँ से 65,234 देशी एवं विदेशी कैडेट्स पास आउट होकर अपने-अपने देश की सेना में सैन्य अधिकारी बन चुके हैं। इनमें 34 मित्र देशों की सेना के 2,914 सैन्य अधिकारी भी शामिल हैं।
- विदित हो कि आईएमएम में होने वाले पासिंग आउट परेड (पीओपी) में बड़ी संख्या में उत्तराखंड के युवा अफसर निकलते हैं। आबादी में अन्य प्रदेशों से काफी छोटा होने के बाद भी अफसर देने में उत्तराखंड देशभर में पहले स्थान पर है।
- पीओपी में इस बार भी उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा कैडेट्स देने वाला राज्य बना है। उत्तर प्रदेश के 68 कैडेट्स पासआउट होकर अफसर बनेंगे। वहीं, उत्तराखंड इस बार दूसरे स्थान पर है। उत्तराखंड के 42 कैडेट्स पासआउट हुए।
- पिछली बार 20 राज्यों के कैडेट पीओपी में शामिल थे, लेकिन इस बार 27 राज्यों के कैडेट्स ने पीओपी में भाग लिया।
- पासिंग आउट परेड में निम्नलिखित कैडेट्स को विभिन्न अवार्ड/पदक मिले-
  - स्वॉर्ड ऑफ ऑनर और गोल्ड मेडल- गौरव यादव (अवलर, राजस्थान)
  - सिल्वर मेडल- सौरभ बधानी (ग्वाल्दम चमोली, उत्तराखंड)
  - ब्रॉन्ज मेडल- आलोक सिंह (कानपुर, उत्तर प्रदेश)
  - सिल्वर मेडल (टीजीसी)- अजय पंत (रानीखेत अल्मोड़ा, उत्तराखंड)
  - श्रेष्ठ विदेशी कैडेट- शैलेश भट्टा (नेपाल) चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बैनर, कोहिमा कंपनी
- भारत सहित अन्य देशों को मिले अधिकारी- भारत-343, भूटान-9, मालद्वीव-4, श्रीलंका-4, मॉरीशस-3, नेपाल-2, म्यांमार-1, बांग्लादेश-1, तजाकिस्तान-1, उज़्बेकिस्तान-1, सूडान-1, तुर्कमेस्तिान-1, किर्गिस्तान-1

नोट :

7708 करोड़ रुपए की लागत से पूर्ण होगा टिहरी झील विकास परियोजना

चर्चा में क्यों ?

11 दिसंबर, 2023 को पर्यटन, धर्मस्व एवं संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने समीक्षा बैठक में कहा कि टिहरी झील विकास परियोजना को 7708 करोड़ रुपए की लागत से पूरा किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद के सभागार में पर्यटन मंत्री ने पर्यटन और संस्कृति विभाग के कार्यों की समीक्षा के दौरान बताया कि टिहरी झील के 42 किमी. क्षेत्रफल को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाएगा।

नोट :

- उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद इस परियोजना की डीपीआर तैयार कर रहा है। परियोजना निर्माण से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही टिहरी ज़िले के 173 गाँवों के 84 हज़ार लोगों को प्रत्यक्ष रूप से लाभ मिलेगा।
- मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि प्रस्तावित रिंग रोड के निर्माण से देश-दुनिया से आने वाले पर्यटकों के लिये टिहरी पहुँचना आसान होगा। झील में सालभर जलक्रीड़ा और साहसिक खेलों का आयोजन को बढ़ावा मिलेगा। इससे सरकार का राजस्व भी बढ़ेगा।
- उन्होंने कहा कि वर्तमान में परियोजना की फिजिबिलिटी सर्वेक्षण के लिये कार्य किया जा रहा है। परियोजना में कोठी से डोगरा चाँटी पुल तक के क्षेत्र को विकसित करने के लिये विभाग द्वारा डीपीआर तैयार की जा रही है।

ज्वालापुर में बनेगा यूनिटी मॉल, शामिल होगी सभी राज्यों की एक-एक दुकान

चर्चा में क्यों ?

12 दिसंबर, 2023 को उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि हरिद्वार के ज्वालापुर में 164 करोड़ रुपए की लागत से यूनिटी मॉल बनेगा, जिसमें देश के सभी राज्यों की एक-एक दुकान होगी।

प्रमुख बिंदु

- वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण जल्द ही हरिद्वार-दिल्ली हाईवे पर ज्वालापुर में इस यूनिटी मॉल का निर्माण करेगा।
- उन्होंने कहा कि यूनिटी मॉल के खुलने से हरिद्वार आने वाले पर्यटक व श्रद्धालुओं को अपने घर लौटने के दौरान उत्तराखंड ही नहीं, देश के किसी भी राज्य का मशहूर हस्तशिल्प सामान और पारंपरिक वस्त्र एक ही छत के नीचे उपलब्ध हो सकेगी।
- उन्होंने बताया कि मॉल के लिये रानीपुर झाल के समीप जगह चिह्नित कर ली गई। डीपीआर से लेकर डिजाइन भी फाइनल हो चुका है।
- यूनिटी मॉल के खुलने से उत्तराखंड के पारंपरिक उत्पादों को भी नई पहचान मिलेगी। बहुमंजिला मॉल में ओपन सिनेमा हाल भी बनाया जाएगा, जिसमें किसी भी तल से लघु नाटिका या फिल्म देखी जा सकेगी।

नोट :

मिनी गैस एजेंसी योजना

चर्चा में क्यों ?

14 दिसंबर, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तराखंड ग्राम्य विकास विभाग ने प्रदेश के सुदूर पर्वतीय क्षेत्रों में रसोई गैस सिलिंडर खत्म होने पर उसे रिफिल कराने के लिये 'मिनी गैस एजेंसी योजना' शुरू की है।

प्रमुख बिंदु

- प्रदेश में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शुरू होने के बाद घर-घर गैस सिलिंडर तो पहुँच गए हैं, लेकिन खासकर पर्वतीय क्षेत्रों में अब भी सिलिंडर रिफिल कराने के लिये लंबा इंतजार करना पड़ता है या कई किमी. दूर जाना पड़ता है। इस समस्या से पार पाने के लिये ग्राम्य विकास विभाग ने मिनी गैस एजेंसी योजना शुरू की है।
- अपर सचिव एवं ग्राम्य विकास विभाग आयुक्त आनंद स्वरूप ने बताया किमिनी गैस एजेंसी का संचालन स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएँ करेंगी, इन्हें 'ईंधन सखी' नाम दिया गया है।
- पायलट प्रोजेक्ट के तौर चार ज़िलों में यह योजना शुरू हो चुकी है। शीघ्र ही योजना अन्य ज़िलों में भी शुरू होगी। अभी तक उत्तरकाशी की 40, टिहरी की 16 और हरिद्वार की पाँच महिलाओं सहित कुल 61 ईंधन सखी तैयार हो चुकी हैं।
- एचपी कंपनी की ओर से महिलाओं को मिनी गैस एजेंसी संचालन की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके लिये सरकार ने एचपी कंपनी से करार किया है। आने वाले दिनों में अन्य तेल कंपनियों से भी इस तरह के करार किये जाएंगे।
- मिनी गैस एजेंसी में हर वक्त पाँच भरे हुए गैस सिलिंडर उपलब्ध रहेंगे। कंपनी की ओर से हर सिलिंडर पर ईंधन सखी को 20 रुपए तक कमीशन मिलेगा। बर्नर, चूल्हा, इसकी सर्विस, गैस पाइप, नए कनेक्शन देने, डीबीसी कनेक्शन पर भी कंपनी की ओर से कमीशन दिया जाएगा। गाँव-गाँव में प्रचार प्रसार करने पर एक हज़ार रुपए अलग से मिलेंगे।
- ग्राम्य विकास विभाग आयुक्त आनंद स्वरूप ने बताया कि इस योजना के दो उद्देश्य हैं। पहला स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की आय बढ़ाना और दूसरा सुदूर क्षेत्रों में आसानी से गैस पहुँचाना।

राज्यस्तरीय प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को राष्ट्रीय खेलों में मिलेगी सीधे एंट्री

चर्चा में क्यों ?

14 दिसंबर, 2023 को राज्यस्तरीय प्रतियोगिता को लेकर हुई बैठक में विशेष प्रमुख सचिव अमित सिन्हा ने बताया कि प्रदेश में अगले साल राष्ट्रीय खेलों से पहले होने वाली राज्यस्तरीय प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को राष्ट्रीय खेलों में सीधे एंट्री मिलेगी। बेशक वे किसी एसोसिएशन से संबंद्धता रखते हों या नहीं।

प्रमुख बिंदु

- विशेष प्रमुख सचिव अमित सिन्हा ने कहा कि नियमानुसार फेडरेशन के माध्यम से खिलाड़ियों को राज्यस्तरीय प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। यदि कोई खिलाड़ी शानदार प्रदर्शन करता है, तो उसे राष्ट्रीय खेलों में सीधे प्रवेश मिलेगा।
- राष्ट्रीय खेलों से पहले होने वाली राज्यस्तरीय प्रतियोगिता में, जो चैंपियन हैं, उन्हें मौका मिलेगा। इसके साथ ही इसके राज्यस्तरीय प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा।
- विभिन्न प्रतियोगिता में जो पहले, दूसरे, तीसरे व चौथे स्थान पर रहे हैं, उनमें से भी खिलाड़ियों को चयनित कर उन्हें खेलने का अवसर दिया जाएगा।
- विशेष प्रमुख सचिव ने कहा कि उत्तराखंड राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कर रहा है, जिसे देखते हुए बेहतर खेलने वाला राज्य का कोई भी खिलाड़ी प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर सकेगा।
- विभाग के अधिकारियों के मुताबिक राज्य ओलंपिक खेल जनवरी और फरवरी में होंगे। देहरादून सहित विभिन्न ज़िलों में इन खेलों का आयोजन किया जाएगा। इसी के आधार पर खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा।

नोट :

राज्य की विद्युत व्यवस्था और पॉवर ट्रांसमिशन नेटवर्क की मजबूती हेतु एशियन विकास बैंक ने 200 मिलियन डॉलर की ऋण को स्वीकृति दी

चर्चा में क्यों ?

14 दिसंबर, 2023 को नई दिल्ली में एशियन विकास बैंक ने उत्तराखंड में विद्युत व्यवस्था और पॉवर ट्रांसमिशन नेटवर्क की मजबूती हेतु 200 मिलियन डॉलर (करीब 1660 करोड़ रुपए) के ऋण को स्वीकृति देते हुए सरकार के साथ ऋण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया।

प्रमुख बिंदु

- नई दिल्ली में वित्त मंत्रालय के आर्थिक विभाग की संयुक्त सचिव जूही मुखर्जी और भारत में एडीबी के डिप्टी रेजिडेंट मिशन निदेशक होयुन जियोंग ने ऋण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये।
- आर्थिक विभाग की संयुक्त सचिव जूही मुखर्जी ने कहा कि उत्तराखंड की बिजली प्रणाली के बुनियादी ढाँचे को मजबूती व बिजली प्रणाली के नेटवर्क क्षमताओं के विकास, लोड केंद्रों के नवीकरण, ऊर्जा के निर्बाध एकीकरण में इससे सुविधा होगी। राज्य के निवासियों को 24 घंटे बिजली उपलब्ध होगी।
- एडीबी के डिप्टी रेजिडेंट निदेशक होयुन जियोंग ने कहा कि इस योजना के तहत 537 किमी. भूमिगत केबल प्रणाली, बिजली नेटवर्क के आधुनिकीकरण, सब स्टेशन के क्षमता विकास व विद्युत वितरण प्रक्रिया को भी अधिक प्रभावी बनाया जाएगा।
- समझौता ज्ञापन के तहत पॉवर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड (पिटकुल) करीब 850 करोड़ रुपए से पॉवर ट्रांसमिशन के नेटवर्क को मजबूत बनाएगा। वहीं उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यूपीसीएल) करीब 750 करोड़ रुपए से देहरादून शहर की बिजली लाइन को भूमिगत करेगा।
- यूपीसीएल 11 केवी के अलावा कुछ जगहों पर 33 केवी, मुख्य मार्गों व उससे जुड़े सहायक मार्गों की 537 किमी. बिजली लाइन भूमिगत करेगा। वहीं, पिटकुल नए सब स्टेशन बनाने के साथ ही विद्युत लाइन भी बनाएगा।

उत्तराखंड से हुई देश की पहली हिमालयी एयर सफारी की शुरूआत

चर्चा में क्यों ?

16 दिसंबर, 2023 को देश की पहली हिमालयी एयर सफारी की शुरूआत उत्तराखंड से की गई। जायरोकॉप्टर एडवेंचर शुरू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है।

प्रमुख बिंदु

- विदित हो कि हरिद्वार के बैरागी कैंप में जायरोक्राप्टर की उड़ान का सफल ट्रायल किया गया, जिसमें डीएम हरिद्वार धीरज सिंह गर्ब्याल ने उड़ान भरी।
- प्रदेश में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने की यह अनोखी पहल है। जायरोकॉप्टर से एयर सफारी के लिए पर्यटन विभाग को डीजीसीए की मंजूरी मिल गई है।
- उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद राजस एयरो स्पोर्ट्स एवं एडवेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से प्रदेश में जायरोकॉप्टर से एयर सफारी शुरू करेगा। एक सीट एयरोकॉप्टर से पर्यटक हवा में रोमांच करने के साथ ही हिमालय और प्राकृतिक सौंदर्य को करीब से निहार सकते हैं।
- पर्यटन विकास परिषद के अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी अश्विनी पुंडीर ने बताया कि जायरोकॉप्टर से प्रदेश के अनछुए पर्यटन स्थल तक पर्यटक आसानी से पहुंच सकेंगे। साथ ही हिमालय, पर्वतमाला, नदियों के हवाई दृश्य का आनंद ले सकते हैं।
- सिंगल सीटर एयरोकॉप्टर को जर्मनी से खरीदा गया है। इससे साहसिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। शनिवार को हरिद्वार में जायरोकॉप्टर का ट्रायल किया गया।

नोट :

उत्तराखंड को मिला साहसिक पर्यटन में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार

चर्चा में क्यों ?

18 दिसंबर, 2023 को गुजरात के केवडिया में आयोजित कार्यक्रम में एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन आफ इंडिया (एटीओएआई) की ओर से उत्तराखंड को साहसिक पर्यटन में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार प्रदान किया गया।

प्रमुख बिंदु

- विदित हो कि साहसिक पर्यटन में नई पहल और प्रोत्साहन को देखते हुए उत्तराखंड को श्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया गया है। कार्यक्रम में उत्तराखंड के पर्यटन सचिव सचिन कुर्वे ने यह पुरस्कार प्राप्त किया।।
- इस अवसर पर सचिव सचिन कुर्वे ने कहा कि पिछले एक साल में उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद ने राज्य को देश के अग्रणी साहसिक पर्यटन राज्य के रूप में विकसित करने की दिशा में उल्लेखनीय काम किया है।
- टिहरी झील में पहली बार पैराग्लाइडिंग एक्रो फेस्टिवल का आयोजन किया गया। जिसमें 26 देशों के 54 पायलटों ने भाग लिया। इसके अलावा देश में जायरोकॉप्टर से एयरो सफारी की शुरुआत उत्तराखंड से की गई है।
- सचिव ने बताया कि गंगा के अलावा रिवर राफ्टिंग व क्याकिंग के लिये शारदा, अलकनंदा, टोंस, भागीरथी नदी में ऑपरेटर शुल्क में छूट दी गई है। इससे रोज़गार के नए अवसर मिलेंगे।
- उन्होंने बताया कि साहसिक पर्यटन के लिये रिवर राफ्टिंग एवं क्याकिंग, एयरो स्पोर्ट्स, ट्रैकिंग, वोट पैरासेलिंग की नियमावली तैयार की जा रही है।
- राज्य में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिये प्रदेश सरकार का तीर्थाटन के अलावा साहसिक पर्यटन पर फोकस है। रिवर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग, एयरो स्पोर्ट्स, पर्वतारोहण, ट्रैकिंग में उत्तराखंड में काफी संभावनाएँ है।
- राज्य सरकार प्रदेश को साहसिक पर्यटन का डेस्टिनेशन बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। इसके लिये नई पर्यटन नीति में साहसिक गतिविधियों व सेवाओं के लिये शत प्रतिशत सब्सिडी का प्रावधान किया गया।

नोट :

उत्तराखंड को साहसिक पर्यटन में सर्वश्रेष्ठ राज्य का मिला पुरस्कार

चर्चा में क्यों ?

19 दिसंबर 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तराखंड को साहसिक पर्यटन में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार प्रदान किया गया है।

प्रमुख बिंदु

- यह पुरस्कार एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन आफ इंडिया (एटीओएआई) की ओर से उत्तराखंड को प्रदान किया गया।
- यह पुरस्कार कार्यक्रम गुजरात के केवडिया में आयोजित में किया गया था जहां उत्तराखंड के सचिव पर्यटन सचिन कुर्वे ने इस पुरस्कार को प्राप्त किया।
- सचिव पर्यटन सचिन कुर्वे ने बताया कि टिहरी झील में पहली बार पैराग्लाइडिंग एक्रो फेस्टिवल का आयोजन किया गया,जिसमें 26 देशों के 54 पायलटों ने भाग लिया था।
- सचिव पर्यटन सचिन कुर्वे ने बताया कि देश में जायरोकॉप्टर से एयरो सफारी की शुरुआत उत्तराखंड से की गई है।
- विदित हो कि उत्तराखंड में रिवर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग, एयरो स्पोर्ट्स, पर्वतारोहण, ट्रैकिंग में आदि में काफी संभावनाएं है।

नोट :

उत्तराखंड में सड़कों से जुड़ेंगे 100 से अधिक जनसंख्या वाले जनजातीय क्षेत्र

चर्चा में क्यों ?

20 दिसंबर 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन) के अंतर्गत उत्तराखंड के जनजातीय वाले ऐसे क्षेत्रों को सड़कों से जोड़ा जाएगा, जिनकी आबादी 100 से अधिक है।

प्रमुख बिंदु

- इस अभियान के अंतर्गत उत्तराखंड को अभी तक चार सड़कें और आठ पुल मिले हैं।
- पीएम ग्राम सड़क योजना के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कर्मेंद्र सिंह ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत उत्तराखंड में प्रथम चरण में देहरादून जिले की हसनपुर, हरिद्वार की जसपुर चमरिया, चंपावत की खिर्दवाड़ी और पिथौरागढ़ की छिपलतरा बसावटों को सड़क मार्गों से जोड़ने के लिए चयन किया गया है।
- उत्तराखंड में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की नोडल एजेंसी यूआरआरडीए (उत्तराखंड रूरल रोड डेवलपमेंट एजेंसी) को सड़क और पुलों के निर्माण की जिम्मेदारी दिया गया है।
- कर्मेंद्र सिंह ने बताया कि इस योजना के तहत 2 किमी से लेकर 13 किमी तक की सड़क बनाई जाएगी।
- विदित हो कि उत्तराखंड में पांच जनजातियां भोटिया, थारू, जौनसारी, बोक्सा और राजी निवास करती हैं। इन्हें वर्ष 1967 में अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया था। इनमें से बोक्सा और राजी विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) में शामिल हैं।
- गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 15 नवंबर 2023 को जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर खूंटी, झारखंड से इस अभियान की घोषणा की थी।

नोट :

पांच हज़ार मिनी आंगनबाड़ी केंद्र होंगे उच्चीकृत

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में उत्तराखंड की महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने विधानसभा स्थित सभागार में विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में कहा कि प्रदेश की पांच हज़ार मिनी आंगनबाड़ी केंद्र उच्चीकृत होंगे। इससे पांच हज़ार महिलाओं को रोजगार मिलेगा।

प्रमुख बिंदु

- मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि एकल महिला योजना के तहत विधवा, निराश्रित, अविवाहित, तलाकशुदा, परित्यकता, आपदा एवं एसिड अटैक से प्रभावित महिलाओं को स्वरोज़गार के लिए 75 प्रतिशत सब्सिडी का प्रस्ताव कैबिनेट में लाया जाएगा।
- उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की घोषणा के तहत एकल महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु उन्हें स्वरोजगार से जोड़ा जाना है। इसका प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा गया है।
- विभागीय मंत्री ने कहा कि सरकार जरूरतमंद महिलाओं को छत उपलब्ध कराएगी। आपदाग्रस्त एवं छत विहीन महिलाओं के लिए छत देने की योजना पर काम किया जाएगा।
- 24 जनवरी, 2024 को राष्ट्रीय बालिका दिवस पर प्रदेश की सभी मेधावी बालिकाओं को सम्मानित किया जाएगा। इस संबंध में विभाग के अधिकारियों को बालिकाओं की सूची तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।

उत्तराखंड में सख्त भूमि कानून

चर्चा में क्यों ?

उत्तराखंड सरकार द्वारा सख्त भूमि कानूनों को लागू करने की संभावना है, जिससे गैर-मूल निवासियों के लिये राज्य की पहाड़ियों के ग्रामीण इलाकों में जमीन खरीदना और अपना घर बनाना चुनौतीपूर्ण हो जाएगा।

मुख्य बिंदु:

- हिमाचल प्रदेश किरायेदारी और भूमि सुधार अधिनियम, 1972 से प्रभावित प्रस्तावित कानून का उद्देश्य ग्रामीण पहाड़ी क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण को सीमित करके राज्य के हितों की रक्षा करना है।

नोट :

- वर्ष 2003 में, बाहरी लोगों को पहाड़ी इलाकों में 500 वर्गमीटर की सीमा के साथ ज़मीन खरीदने की अनुमति दी गई।
  - बाद की सरकारों ने बड़े पैमाने पर भूमि लेनदेन को रोकने के लिये इस सीमा को घटाकर 250 वर्गमीटर कर दिया।
- वर्ष 2017 में तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र रावत ने पर्वतीय क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करने के लिये इन प्रतिबंधों को हटा दिया था।
- विभिन्न ज़िलों में विरोध प्रदर्शन के कारण राज्य सरकार ने वर्ष 2022 में पूर्व मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाले पैनल द्वारा प्रस्तुत मसौदा रिपोर्ट का अध्ययन करने के लिये पाँच सदस्यीय समिति का गठन किया।
  - रिपोर्ट में राज्य के संसाधनों का दोहन करने वाले बाहरी निवेशकों की चिंताओं को संबोधित करते हुए शहरी क्षेत्रों में भूमि खरीद की सीमा तय करने की सिफारिश की गई है, जिससे पहाड़ियों में भूमि लेनदेन के लिये 12.5 एकड़ की सीमा को बहाल किया जा सकता है।
  - हालाँकि, निवासी इसका समर्थन कर रहे हैं, जिसमें नगरपालिका क्षेत्रों की सीमा 250 वर्गमीटर तक करना और ग्रामीण भूमि की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना शामिल है।

टिहरी में अनेक परियोजनाएँ

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री द्वारा टिहरी में 415 करोड़ रुपए की 160 परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया गया।

मुख्य बिंदु:

- कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने महिला स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को सम्मानित किया और राज्य आंदोलन एवं राज्य के विकास में उत्तराखंड की महिलाओं द्वारा निभाई गई भूमिका पर प्रकाश डाला।
- महिला सशक्तीकरण के लिये राज्य सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों को रेखांकित करने के लिये, मुख्यमंत्री ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिये 30% आरक्षण का उल्लेख किया और मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री आँचल अमृत योजना और मुख्यमंत्री स्वरोज़गार योजना जैसी योजनाओं पर ज़ोर दिया।
- उन्होंने वर्ष 2025 तक उत्तराखंड को नशा मुक्त बनाने के लिये छात्रों को शपथ भी दिलाई है।

चंपावत में विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत ज़िले के टनकपुर के रामलीला मैदान में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर में भाग लिया।

मुख्य बिंदु:

- इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) के तहत 9 महिला समूहों को एक-एक लाख के चेक वितरित किये साथ ही सहकारिता विभाग की 10 साधन सहकारी समितियों एवं 10 महिला लाभार्थियों को NRLM के तहत 13 लाख के चेक वितरित किये गये।
- योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिये प्रश्नोत्तरी, सांस्कृतिक कार्यक्रम और ड्रोन प्रदर्शन आयोजित किये गए। लाभार्थियों की व्यक्तिगत सफलता की कहानियों और उपलब्धियों को साझा करने के लिये 'मेरी कहानी-मेरी ज़ुबानी' जैसे कार्यक्रम भी आयोजित किये गए।
  - मुख्यमंत्री ने नगर पालिका के लिये 11 नए वाहनों को भी हरी झंडी दिखाई.
- जन कल्याण योजनाओं पर केंद्रित भारत संकल्प योजना केंद्र सरकार द्वारा विकसित की गई है।
  - इस यात्रा का संकल्प 2047 तक भारत को हर तरह से विकसित करना है.
- यात्रा के लिये ग्रामीण क्षेत्रों में 19 और शहरी क्षेत्रों में 15 योजनाओं की पहचान की गई है।
  - पहचानी गई योजनाएँ स्वस्थ भारत मिशन, खाद्य सुरक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएँ, उचित पोषण, गरीबों के लिये आवास, वित्तपोषण संबंधी सेवाएँ और सामाजिक सुरक्षा से संबंधित हैं।
- प्रदेश में अब तक 63 हज़ार से अधिक प्रतिभागियों को योजनाओं का लाभ मिल चुका है।

नोट :

उत्तराखंड में जानवरों के हमले

चर्चा में क्यों ?

वन विभाग के आँकड़ों के अनुसार वर्ष 2023 में बाघों और तेंदुओं से जुड़े मानव-वन्यजीव संघर्ष में 43 मौतें देखी गईं।

मुख्य बिंदु:

- भारतीय वन्यजीव संरक्षण सोसायटी (WPSI) ने वर्ष 2023 के दौरान देश में 204 मौतों का आँकड़ा जारी किया है।
  - जनवरी 2000 से दिसंबर 2023 तक, तेंदुए और बाघ के हमलों में कुल 551 लोगों की जान चली गई और 1,833 से अधिक लोग घायल हो गए।
- देश के 53 बाघ अभयारण्यों में से कॉर्बेट टाइगर रिज़र्व (CTR) में बाघों की सबसे अधिक संख्या 260 बताई गई है।
- वर्ष 2018 में बताए गए आँकड़ों की तुलना में उत्तराखंड में बाघों की आबादी 442 से बढ़कर 560 हो गई है। उत्तराखंड में तेंदुओं की अनुमानित संख्या 3,115 है।
- जून 2001 के बाद से, कुल 1,663 तेंदुओं की मौत दर्ज की गई है, जिनमें से कई अन्य कारणों के अलावा दुर्घटनाओं या अंतर-प्रजाति संघर्षों के कारण हुई हैं।

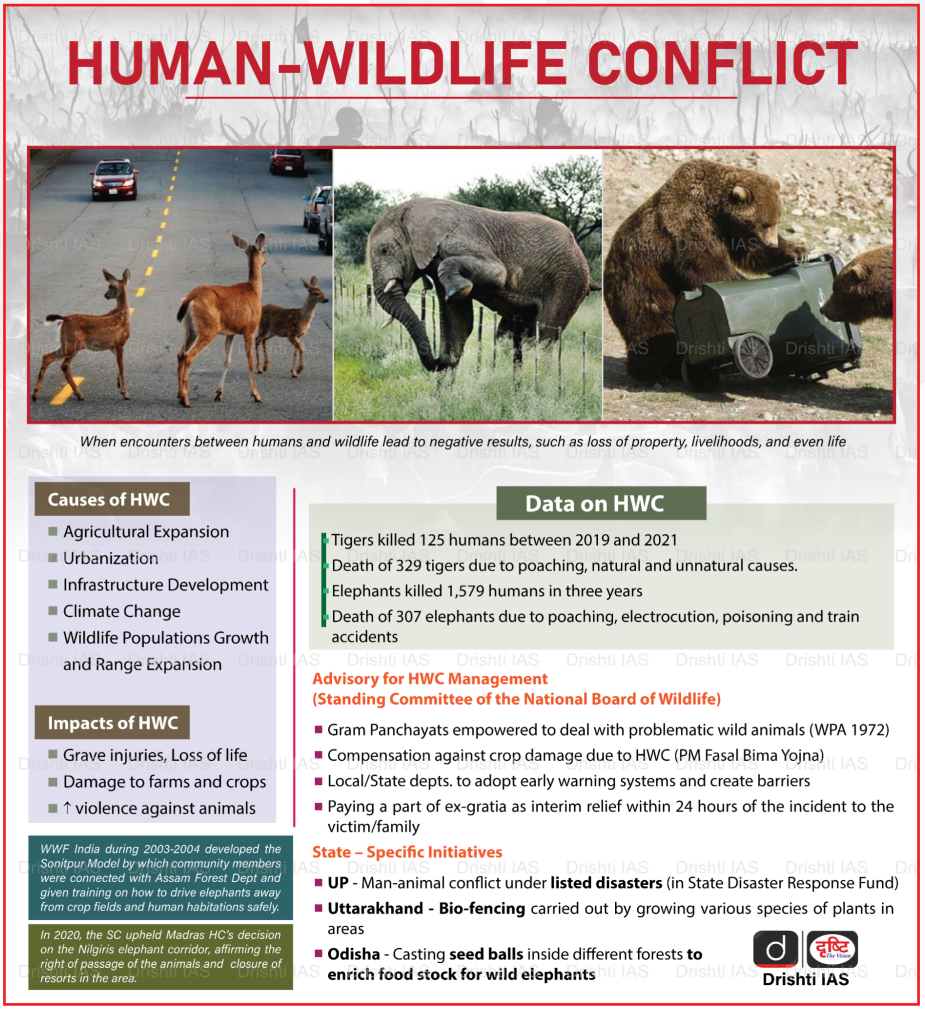

नोट :

उत्तराखंड 'विंटर कार्निवाल'

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति को प्रदर्शित करने के लिये मसूरी में 4 दिवसीय मसूरी में 'विंटर कार्निवाल', स्टार नाइट, फूड फेस्टिवल का होगा आयोजन किया गया।

मुख्य बिंदु:

- कार्निवल ने लोकप्रियता हासिल की और पर्यटकों तथा स्थानीय लोगों के लिये एक प्रमुख आकर्षण बन गया, साथ ही पर्यटन को बढ़ावा मिला एवं स्थानीय व्यवसायों को लाभ हुआ।
- इस "विंटर कार्निवल" ने बड़े पैमाने पर लोकप्रियता हासिल की और पर्यटकों एवं स्थानीय लोगों के लिये एक प्रमुख आकर्षण बन गया है। इसने पर्यटन को बढ़ावा देने और स्थानीय व्यवसायों को लाभ पहुँचाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
- इस वर्ष के उत्सव का विषय 'मोटे अनाजों और फसल से बने व्यंजनों की एक विस्तृत श्रृंखला' है।
- इस कार्यक्रम में खाद्य उत्सव के साथ-साथ कई संगीत और सांस्कृतिक प्रदर्शन भी शामिल हैं।

नोट :